बेमौसम बारिश...

बदलते मौसम की चेतावनी

कभी भारत में वर्षा 'ऋतु' कही जाती थी – खुशहाली और जीवन का प्रतीक। आज वही वर्षा अचानक आने वाली आपदा बन चुकी है। कहीं बाढ़ से तबाही, तो कहीं महीनों तक सूखा – मौसम का संतुलन बिगड़ चुका है। यह केवल प्रकृति का रोष नहीं, बल्कि हमारे विकास मॉडल का परिणाम है, जिसने पर्यावरण को नीतियों के हाशिए पर धकेल दिया है।

भारत में मानसून के बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने सामान्यतः शुष्क माने जाते हैं। किसान खरीफ की फसल काटने और रबी की तैयारी में जुटे होते हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों से मौसम के इस चक्र ने अपनी पहचान ही बदल दी है। जहाँ पहले बारिश का एक निश्चित समय होता था, वहीं अब बेमौसम बारिश ने खेती, जनजीवन और अर्थव्यवस्था–तीनों को संकट में डाल दिया है। बेमौसम बारिश अब अपवाद नहीं, बल्कि नई समस्याएँ बनती जा रही है। यह केवल प्रकृति की मनमानी नहीं, बल्कि हमारी पर्यावरणीय लापरवाही का परिणाम है। यदि समय रहते हमने सतत विकास और जलवायु संवेदनशील नीतियाँ नहीं अपनाईं, तो आने वाले वर्षों में यह आफत हमारी स्थायी सच्चाई बन जाएगी।

बेमौसम बारिश का सबसे बड़ा असर कृषि पर पड़ता है। खरीफ की फसलें जैसे धान, कपास, सोयाबीन और अरहर कटाई के समय पानी में भीगकर खराब हो जाती हैं। भंडारण न होने के कारण खुले खेतों में रखी फसलें सड़ जाती हैं। रबी की बुवाई भी प्रभावित होती है, क्योंकि अधिक नमी और जलभराव से बीज अंकुरण में दिक्कत आती है। किसानों के लिए यह दोहरी मार होती है–एक तरफ लागत बढ़ती है और दूसरी ओर पैदावार घटती है।

बेमौसम बारिश केवल खेतों तक सीमित नहीं रहती। शहरों में सड़कों पर जलभराव, यातायात जाम और बिजली कटौती जैसी समस्याएँ आम हो जाती हैं। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने कच्चे मकानों और सड़क निर्माण कार्यों को भारी नुकसान पहुँचाया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह केवल 'बेमौसम बारिश' नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की स्पष्ट चेतावनी है। समुद्री तापमान बढ़ने से मानसूनी

धाराओं का संतुलन बिगड़ रहा है। एल नीनो और ला नीना जैसे वैश्विक प्रभाव भारतीय मौसम प्रणाली को अस्थिर बना रहे हैं। उत्तर भारत में मानसून की वापसी देर से हो रही है, जिससे अक्टूबर-नवंबर तक बारिश खिंच जाती है।

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण

भारत में मौसम का सीधा असर जीडीपी पर पड़ता है। फसलों के नुकसान से बाजार में अनाज और सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं। ग्रामीण आय घटने से उपभोग में कमी आती है, जिससे औद्योगिक मांग पर भी असर होता है।

व्यापारी और परिवहन क्षेत्र, खराब मौसम में सब्ज़ी, फल, अनाज और कपास जैसी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होती है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को नुकसान होता है क्योंकि रास्ते बंद या खराब हो जाते हैं। व्यापारियों को माल सड़ने या देर से पहुँचने के कारण हानि उठानी पड़ती है।फसल हानि पर मुआवज़ा, सड़क मरम्मत, राहत कार्यों में भारी खर्च आता है। इससे सरकारी बजट पर दबाव बढ़ता है और महंगाई में उछाल आता है।

१. किसान - सबसे बड़ा नुकसान झेलने वाला वर्ग, फसलें खराब होनाः बेमौसम बारिश आमतौर पर फसल कटाई के समय होती है। इस दौरान धान, कपास, सोयाबीन, टमाटर, प्याज जैसी फसलें पानी में भीगकर सड़ जाती हैं।

२. भंडारण में हानि, खुले में रखी फसलें या मंडी तक पहुँचने से पहले ही खराब हो जाती हैं।

३. बीज और बुवाई प्रभावितः, अधिक नमी या जलभराव से रबी की बुवाई (गेहूं, चना, सरसों) में देरी होती है।

४. आर्थिक संकट, किसानों की मेहनत, उर्वरक, बीज और मजदूरी पर खर्च बढ़ता है, जबकि पैदावार घट जाती है।

५. कर्ज़ का बोझ और आत्महत्या जैसे चरम कदमों तक बात पहुँच जाती है।

६. ग्रामीण मजदूर और दैनिक वेतनभोगी, खेती ठप होने से मजदूरी के मौके कम हो जाते हैं।

७. निर्माण कार्य, सड़क मरम्मत, और छोटे ठेकेदार काम बंद कर देते हैं। इससे इन परिवारों की आमदनी अचानक रुक जाती है, खासकर उन इलाकों में जहाँ वैकल्पिक रोजगार नहीं होता।

८. शहरी निम्नवर्ग और झुग्गी-बस्ती के लोग, बेमौसम बारिश से जलभराव, छतों से पानी रिसना, और बीमारियाँ बढ़ जाती हैं।

९. खुले नालों और गंदे पानी से डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार जैसे रोग फैलते हैं।

१०. रोज़ कमाने-खाने वाले लोगों की आवागमन और काम पर जाने की क्षमता प्रभावित होती है।

भारत में पिछले दस वर्षों में बारिश के पैटर्न में जबरदस्त परिवर्तन दर्ज किए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार – देश में असामान्य वर्षा की घटनाएँ पिछले दशक में ६५% बढ़ी हैं। जहाँ कभी वर्षा सीमित समय में होती थी, अब वह कम दिनों में ज़्यादा मात्रा में हो रही है – जिससे फ्लैश फ़्लड जैसी आपदाएँ आम हो गई हैं। २०२५ की मानसून रिपोर्ट बताती है कि इस साल देश के १४ राज्यों में सामान्य से ३०% अधिक बारिश हुई, जबकि ९ राज्यों में ४०% से कम।

राज्यवार परिदृश्यः

केरल – 'हरियाली के बीच तबाही'

केरल २०१८ से लगातार अत्यधिक वर्षा और भूस्खलन से जूझ रहा है। माउंटेन कटिंग, निर्माण कार्य और जंगलों की कटाई ने वर्षा जल को रोकने की प्राकृतिक क्षमता खत्म कर दी। पर्यावरणविद कहते हैं – 'केरल विकास के नाम पर अपनी भूगोलिक सुरक्षा खो चुका है।'

महाराष्ट्र – 'मराठवाड़ा में सूखा, कोकण में बाढ़'

महाराष्ट्र दो विपरीत तस्वीरें दिखाता है –

कोकण में भारी वर्षा और बाढ़, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखा। यह असंतुलन भूमिगत जल स्तर को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे किसान आत्महत्याओं की संख्या बढ़ी है।

असम – 'ब्रह्मपुत्र का प्रकोप'

असम हर साल ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से त्रस्त है। इस बार २०२५ में भी असम के ३० जिलों में बाढ़ ने २५ लाख लोगों को प्रभावित किया। वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लेशियर पिघलने और अत्यधिक वर्षा – दोनों मिलकर नदियों को उग्र बना रहे हैं।

उत्तराखंड – 'पहाड़ अब टूटने लगे हैं'

उत्तराखंड में बारिश अब आपदा का पर्याय बन गई है। जमीन खिसकना, नदी का रुख बदलना और ग्लेशियर झील फटना – सब जलवायु असंतुलन के परिणाम हैं। जोशीमठ जैसे शहर धीरे-धीरे धंस रहे हैं – यह हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए खतरे की घंटी है।

कोल्हापुर जिले में रविवार सुबह से सोमवार सुबह से बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मंगलवार तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। जिले के लिए दो दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्व-मध्य अरब सागर में, कम दबाव का क्षेत्र मुंबई से ४०० किमी दक्षिण-पश्चिम में गहरे दबाव में बदल रहा है, जिससे कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बारिश हो रही है।

अगले पांच दिनों के दौरान कम दबाव का क्षेत्र उत्तर और उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र सोमवार को गहरे कम दबाव के क्षेत्र में चला जाएगा और सोमवार को मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे कम दबाव के क्षेत्र में चला जाएगा। इसलिए, दक्षिण भारत के साथ-साथ महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है क्योंकि कल, मंगलवार को इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इस बीच, कोल्हापुर में रविवार सुबह बारिश हुई। दोपहर में थोड़े देर के ब्रेक के बाद शाम को तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से फसलें प्रभावित हो रही हैं। दिवाली की छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए कोल्हापुर आए पर्यटक रविवार को बारिश के कारण फंस गए। १०/२७/२५, रात ९:०१ बजे कोल्हापुर जिला अलर्ट बनाम 'येलो अलर्ट'

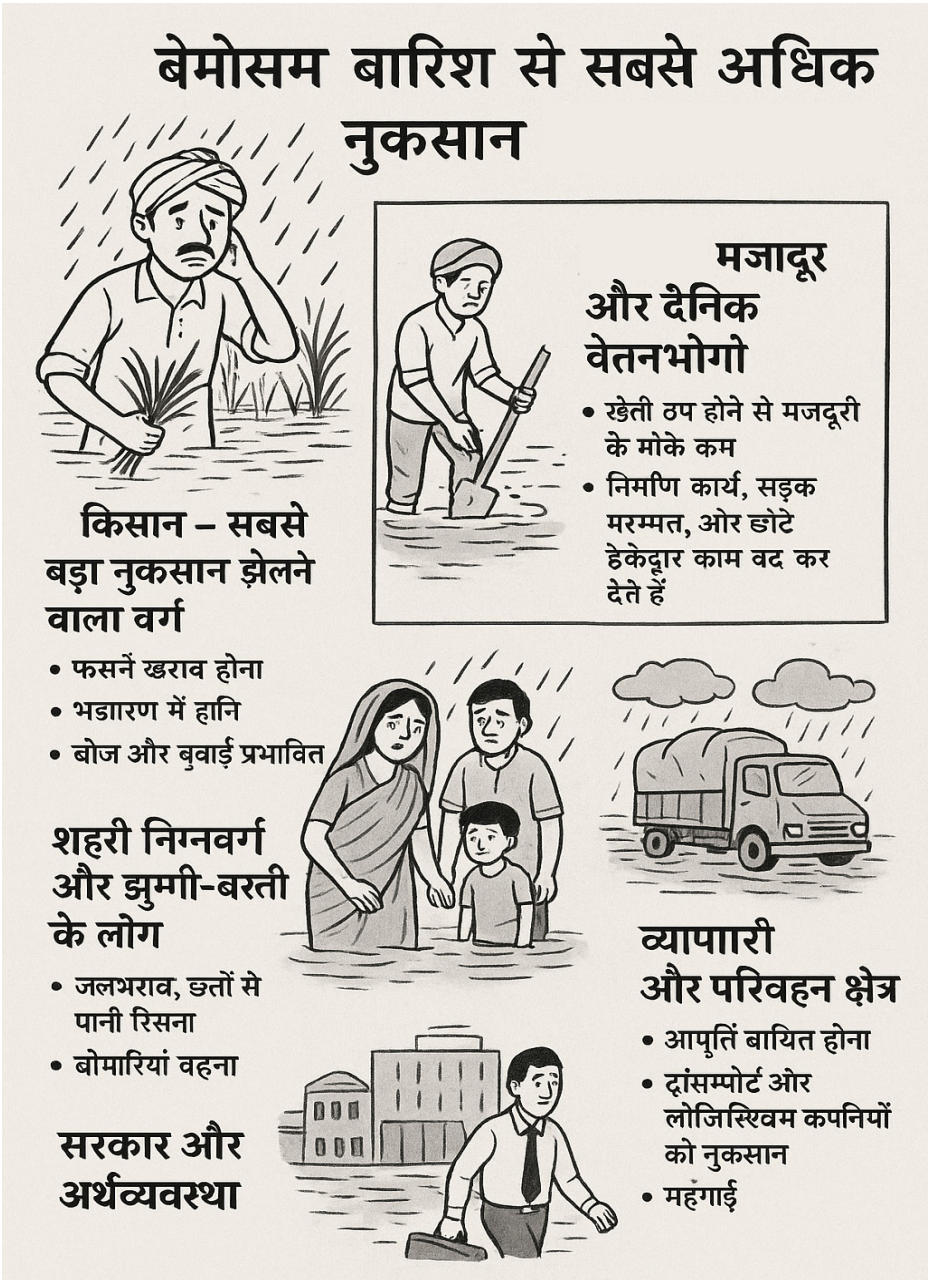

देश के अधिकांश राज्यों में अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई बारिश मई में भी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बेमौसम बारिश ने भले ही आम लोगों को गर्मी से राहत दे दी हो लेकिन किसानों के लिए आफत बन रही है। खासतौर पर उन किसानों के लिए जिन्होंने अभी तक गेहूं नहीं काटा था या जिसकी गेहूं की कटी फसल खेत में रखी हो। लेकिन अब लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मई के महीने में मूसलाधार बारिश क्यों हो रही? मौसम वैज्ञानिक डॉ. एमआर रानालकर ने कहा कि आमतौर पर गर्मी के समय पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। इसी के चलते बेमौसम बारिश हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के रूप में चक्रवाती सर्कुलेशन निचले और ऊपरी क्षोभमंडल स्तरों में मध्य पाकिस्तान पर स्थित है। निचले क्षोभमंडल में दक्षिण पाकिस्तान और इससे सटे पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और दूसरा दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर निचले क्षोभमंडल स्तर पर बना हुआ है। ये क्षोभमंडलीय स्तरों में पूर्वी विदर्भ से तमिलनाडु के अंदरूनी क्षेत्र में हवाओं के बदलाव से मौसम बदला हुआ है। इसका असर अगले तीन से चार दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा। अल नीनो की वजह से भी मौसम पर प्रतिकूल असर बता दें कि प्रशांत महासगार में पेरू के पास सतह के गर्म होने की घटना अल नीनो कहलाती है। अल नीनो की वजह से समंदर के तापमान, वायुमंडल में बदलाव होता है और इस बदलाव की वजह से समंदर का तापमान ४-५ डिग्री तक बढ़ जाता है। अल नीनो की वजह से पूरी दुनिया के मौसम पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

कई जिलों में बारिश की संभावना' दिल्ली में बुधवार और गुरुवार को भी बारिश के आसार मौसम विभाग ने दिल्ली में आगामी दो दिनों के मौसम की जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आसमान में बादल छाए रहने के आसार हैं व कहीं हल्की व कहीं मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ३० से ४० किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। गुरुवार को भी आसमान में बादल छाए रहने व हल्की बारिश की संभावना है। इन १२ राज्यों में भी बारिश के आसार मौसम विभाग ने १२ राज्यों के लिए अगले २४ घंटे में बारिश की संभावना जताई है। जिन राज्यों में बारिश होने के आसार हैं उनमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र में बारिश के साथ ओला गिरने के आसार है।

महाराष्ट्र पर असामान्य बारिश का प्रभाव

१. कृषि पर सबसे गहरा असर

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी लगभग १६% है, और राज्य के ७०% किसान मानसून पर निर्भर हैं। अक्टूबर में हो रही तेज़ बारिश ने खरीफ़ फसल को कटाई से पहले ही तबाह कर दिया।

प्रमुख फसलें जो प्रभावित हुईं:

फसल	क्षेत्र	प्रभाव
सोयाबीन	मराठवाड़ा, विदर्भ	कटाई से ठीक पहले खेतों में सड़ गई, कपास (Cotton) यवतमाल, अमरावती,
अकोला	अधिक नमी से फूल झड़ गए	
धान (Rice)	कोकण, रायगढ़, ठाणे,	
खेतों में जलभराव, अंकुर सड़ गए		
तुअर (अरहर)	लातूर, बीड,नई फसल की बुवाई में देरी	

राज्य सरकार की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, करीब १८ लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है।

२. कोकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में शहरी बाढ़

मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, और रायगढ़ में

अक्टूबर के मध्य तक २००-३०० मिमी अतिरिक्त वर्षा दर्ज की गई।

इसका कारण –समुद्र का बढ़ा तापमान लगातार निम्न दाब क्षेत्र (low-pressure systems) और समुद्री नमी की पुनरावृत्ति

मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भरा रहा,

लोकल ट्रेनें बाधित रहीं

गोवा हाइवे पर भूस्खलन के कारण यातायात रुका

३. मराठवाड़ा में दोहरी मारः सूखा और फिर बाढ़

मराठवाड़ा (लातूर, बीड, उस्मानाबाद) में जून-जुलाई में बहुत कम बारिश हुई थी, लेकिन सितंबर-अक्टूबर में अचानक भारी वर्षा हुई। इससे पहले सूखा, फिर बाढ़ जैसी स्थिति बनी फसलें नष्ट, जलस्रोतों में गाद जमने लगी और किसान कर्ज़ के जाल में फिर फँस गए।

४. बिजली व ग्रामीण ढांचे पर असर

भारी बारिश से कई जगह विद्युत तार और ट्रांसफॉर्मर डूबे, ग्रामीण सड़कों और पुलों को नुकसान, राहत दलों को पहुँचने में कठिनाई राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार केवल अक्टूबर २०२५ में अब तक २८ लोगों की मौत और ५० से अधिक घायल हुए हैं।

५. जलवायु का नया पैटर्नः मॉनसून का खिंचना

महाराष्ट्र में मानसून अब लगभग १५-२० दिन अधिक लंबा चल रहा है। IMD (भारतीय मौसम विभाग) का डेटा बताता है कि पिछले १० वर्षों में ६ बार अक्टूबर के बाद तक मानसून सक्रिय रहा है। औसत तापमान बढ़ने से मॉनसून विदाई की तिथि लगातार आगे खिसक रही है।

६. नीतिगत चुनौती

राज्य सरकार ने 'Climate Action Plan २०२४-२०३०' बनाया है,

लेकिन कार्यान्वयन धीमा है। जलनिकासी सुधार की योजनाएँ अधूरी, किसानों के लिए बीमा भुगतान में देरी और आपदा राहत का असमान वितरण, इससे जनता में असंतोष और किसानों में असुरक्षा की भावना गहरी हो रही है।

इसके अलावा दिल्ली, केरल तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

मराठवाड़ा में भारी वर्षा कितनी होती है? मई में बेमौसम बारिश शुरू होने के बाद मराठवाड़ा में बारिश नहीं रुकी। आम तौर पर, वापसी की बारिश मराठवाड़ा में बांधों को भर देती है। हालांकि, मराठवाड़ा में पिछले पांच सालों में बारिश में बदलाव आया है। यह औसत से ऊपर गिर रहा है। इसके अलावा, अल्पावधि में बारिश की मात्रा भी बढ़ गई है। पहले चरण में नांदेड़ जिले के मुखेड़, कंधार, बिलोली सहित कुछ तालुकों में बारिश ने कहर बरपाया। इतनी बारिश होती थी कि बाढ़ के दौरान जमीन पर मिट्टी की परत गायब हो जाती थी। गांव में नदी के किनारे कुछ जगहों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं। कुछ खेत गाद से भरे हुए थे। प्रशासनिक स्तर के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक १२,३९४ किसानों की ४,१३६ हेक्टेयर भूमि का कटाव हुआ है। हर दिन नए परिवर्धन किए जा रहे हैं। धाराशिव जिले के परंडा और भूम तालुकों में यह संख्या अब बढ़ती जा रही है। किसानों को कृषि फसलों के नुकसान को सहन करने की आदत थी। लेकिन अब हजारों किसानों के पास जमीन नहीं है। इसलिए, इन बाढ़ के कारण, कृषि में पूंजी का नुकसान अधिक होता है। इसलिए अगर गीले सूखे की घोषणा की जाती है तो और मदद मिलेगी, यह मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने की गई थी।

भारी बारिश और बाढ़ में मरने वालों के परिजनों को दो दिन से ज्यादा समय तक घर में पानी रहने या घर बह जाने पर चार लाख रुपये और पांच हजार रुपये प्रति परिवार दिए जाते थे। इसे २०२४ में संशोधित किया जाएगा और तत्काल सहायता के रूप में १०,००० रुपये दिए जा रहे हैं। मुख्य मुद्दा कृषि फसलों का नुकसान है। शुष्क क्षेत्रों के लिए ८,५०० रुपये प्रति हेक्टेयर, अंकुरित फसलों के लिए १७,००० रुपये, बारहमासी फसलों के लिए २२,५०० रुपये और रेशम उत्पादन के लिए ६,००० रुपये प्रति हेक्टेयर की दर तय की गई है। चुनाव से पहले, शुष्क भूमि फसलों के लिए सहायता की दर क्रमशः १३,६०० रुपये, बागवानी फसलों के लिए २७,००० रुपये और बारहमासी फसलों के लिए ३६,००० रुपये थी। तथापि, राष्ट्रीय आपदा राहत की ये दरें सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान की गई दरों से कम हैं। यानी सवाल उठ रहा है कि पहले से तय की गई सहायता दरों को क्यों घटाया गया। वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बाढ़ निरीक्षण के दौरान दिया गया बयान कि 'पैसा नहीं लाया जा सकता' इस मदद के लिए खबरों में है। इसलिए विपक्ष भी मांग कर रहा है कि शक्तिपीठ हाईवे को खत्म कर किसानों को पैसा दिया जाए। सांगली-कोल्हापुर बाढ़ के दौरान दिए गए विशेष फंड की तरह ही एक विशेष फंड की मांग की जा रही है। इस तरह की एक अलग फंड मानसिकता 'गीले सूखे' की मांग कर रही है।

नुकसान कब तक रहेगा? नुकसान का विभिन्न स्तरों पर विश्लेषण किया जा रहा है। कृषि नुकसान के अनुमान हर दिन बदल रहे हैं। चूंकि कई क्षेत्रों में पंचनामा करना संभव नहीं है, इसलिए 'ड्रोन फिल्मांकन' या फोटोग्राफी के आधार पर ही पंचनामा करने के निर्देश हैं, लेकिन रोजाना बारिश के कारण ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए भले ही सरकार ने पंचनामा के बाद दिवाली के बैंक खाते में आने का शुभ मुहूर्त तय कर दिया हो, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है,

एक तरफ बाढ़ के दौरान किसानों का केवाईसी कराने के लिए मंडलायुक्त को बैठक करनी पड़ी। इसलिए, यह संभावना नहीं है कि मराठवाड़ा को जो भी मदद मिलेगी उससे वह तुरंत ठीक हो जाएगा। कई इलाकों में झीलें फट गई हैं। स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की दीवारें ढह गई हैं। रेल पटरियों के नीचे बजरी बह गई है। गाद कुएं में चली गई है। किसानों के ड्रिप सिंचाई पाइप और मोटरें बह गई हैं। नतीजतन, नदी के किनारे बागवानों और किसानों की स्थिति काफी खराब हो गई है। इस मानसून में मराठवाड़ा में २,५३४ मवेशियों की मौत हो गई। भूम तालुका में दूध का उत्पादन विशेष रूप से अधिक है, जहां जर्सी गायों की मृत्यु दर अधिक है। चारे के गीले होने से दूध उत्पादन में कमी आई है। नदी के किनारे के गांवों में मुर्गी और मुर्गी के पौधों की बकरियां बह गई हैं। इससे कृषि व्यवसाय भी काफी प्रभावित हुआ है। इन परियोजनाओं को तत्काल पुनर्जीवित करना संभव नहीं है। इस तरह के बुनियादी ढांचे और धन सृजक योजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत पैसा लगेगा। उस फंड को प्राप्त करने के लिए क्या केंद्र सरकार मराठवाड़ा का दर्जा स्वीकार करेगी? स्थिति गंभीर होने के कारण केंद्र सरकार से धन की मांग की गई है।

केंद्र सरकार से इस तरह का फंड हासिल करने के लिए खास प्रयास करने होंगे। मराठवाड़ा में भी इस बात को लेकर उत्सुकता है कि यह फंड कब जारी किया जाएगा क्योंकि अगले कुछ दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। लोकसभा में मराठवाड़ा की राजनीतिक ताकत महा विकास अघाड़ी के पक्ष में है। छत्रपति संभाजीनगर को छोड़कर अन्य सात लोकसभा क्षेत्रों से कोई भी सांसद नहीं है। इसलिए राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि भारी बारिश में विशेष कोष की संरक्षकता स्वीकार करना जरूरी होगा क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें इस गुस्से को बढ़ते हुए रखने का जोखिम नहीं उठा सकती हैं। हालांकि अब तक २,१०० करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, लेकिन यह बहुत कम है।

Wholesale Furniture Market

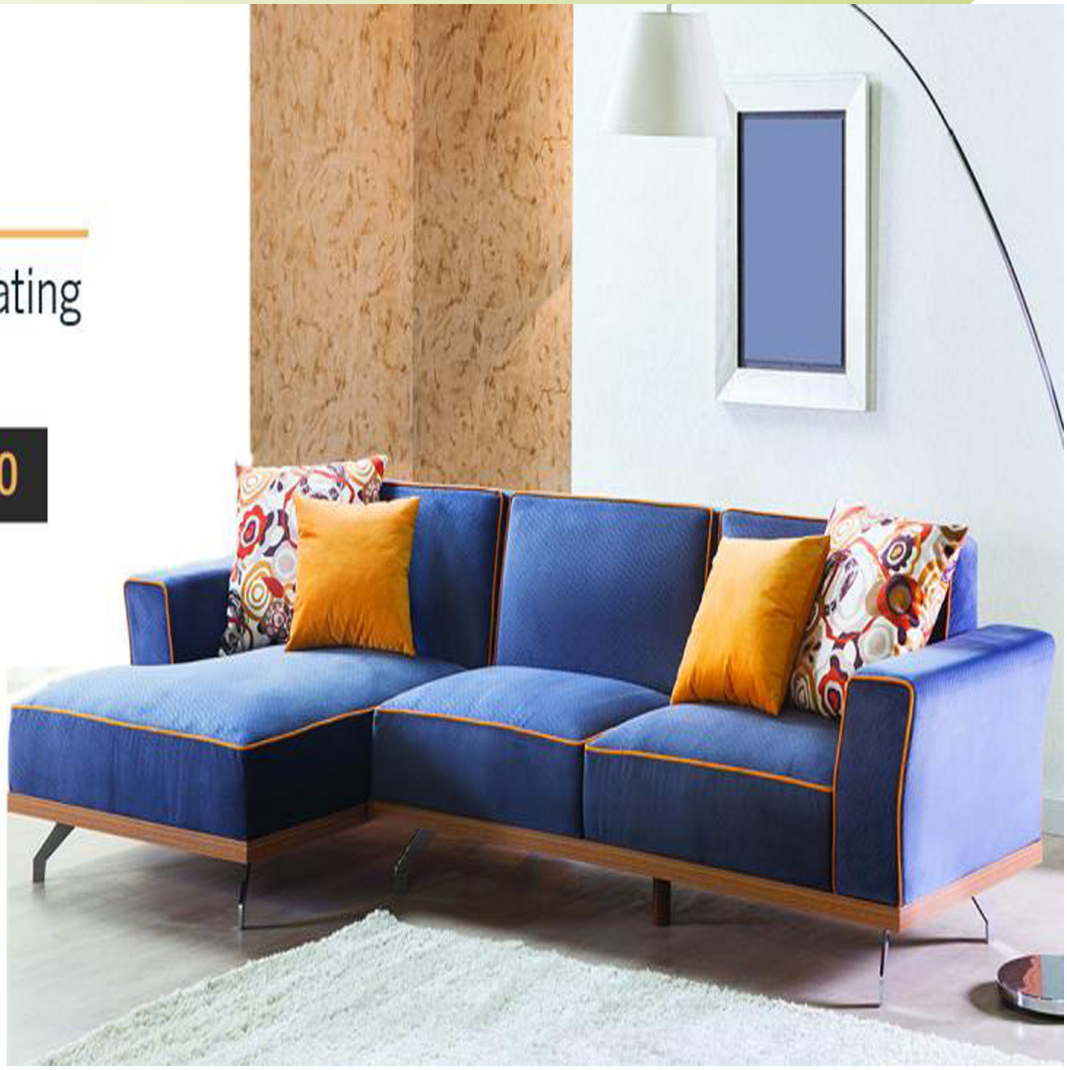

Ulhasnagar,Mumbai

सस्ते फर्नीचर के 5 थोक बाजार

फर्नीचर खरीदिए आधे दामों पर

एक से बढ़कर एक एंटीक आइटम

अंतहीन आपदाएं जान-माल ही नहीं, बल्कि खेत, फसलें, बुनियादी ढांचा और समूची आजीविकाएं भी अनवरत आपदाओं की भेंट चढ़ रही हैं. संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की एक ताजा रिपोर्ट से पता चला कि जलवायु से जुड़ी आपदाओं की वजह से भारत को १९९८ से २०१७ तक पिछले २० साल में ७९.५ अरब डॉलर (करीब ७ लाख करोड़ रुपए) का नुक्सान हो चुका है.

करेंसी और फाइनेंस पर आरबीआइ की २०२३-२४ की रिपोर्ट का अनुमान है कि अत्यधिक गर्मी और बरसात से गंवाए गए काम के घंटों से देश को २०३० तक जीडीपी के ४.५ फीसद तक का नुक्सान उठाना पड़ सकता है. जान-माल का नुक्सान भी इतना ही भीषण है. २०२४-२५ में जलवायु से जुड़ी ३,०८० मौतें हुईं, जो एक दशक में सबसे ज्यादा थीं, जबकि इससे पहले के साल यह आंकड़ा २,६१६ था.

जलवायु परिवर्तन के प्रति अतिसंवेदनशील देशों में भारत अब शीर्ष १० में है. आइएमडी ने तस्दीक की है कि बीते दो दशक में देश का औसत तापमान २००१ में २५.०५ डिग्री सेल्सियस से बढ़कर २०२४ में २५.७४ डिग्री सेल्सियस हो गया है. ०.६९ डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भले मामूली लगे लेकिन जलवायु विज्ञान में आधी डिग्री का मतलब सहने लायक और बर्बादी के बीच का फर्क हो सकता है. आइपीई ग्लोबल और एसरी इंडिया की जून २०२५ की रिपोर्ट 'वेदरिंग द स्टॉर्म' से पता चला कि देश के शहरों में २०३० तक लू के दिनों में दोगुना और बारिश की तीव्रता में ४३ फीसद का इजाफा होगा.

आइपीई ग्लोबल के क्लाइमेट ऐंड सस्टेनेबिलिटी प्रमुख अबिनाश मोहंती बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन से कैसे कई सारे मौसमी व्यवधान पैदा हो रहे हैं. पूरे मॉनसून की बारिश अब एक या दो दिनों में हो जाती है, जो केरल, चेन्नै, मुंबई और बेंगलूरू में बाढ़ की मुख्य वजह है. वे यह भी कहते हैं कि देश के ७३८ जिलों में से ८५ फीसद मौसम की उग्र घटनाओं के ज्वलंत स्थल हैं, जिनमें ४५ फीसद में वह देखा जा रहा है जिसे जलवायु की बोलचाल में 'स्वैपिंग ट्रेंड' कहा जाता है.

इसका मतलब है कि पारंपरिक रूप से बाढ़ की बहुलता वाले क्षेत्रों में बार-बार और तीव्र सूखे पड़ रहे हैं और सूखे की बहुलता वाले क्षेत्रों में बार-

आईपीसीसी की यह रिपोर्ट भारत और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए और चिंताजनक है, क्योंकि इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि वैश्विक तापमान में यदि दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो इसका सबसे अधिक असर प्राकृतिक आपदाओं और खाद्य उत्पादन और आजीविका के अवसरों पर पडेग़ा। जलवायु परिवर्तन वैश्विक खाद्य उत्पादन को गंभीरता से प्रभावित करेगा, जैसे सूखे के रूप में, वर्षा की वृद्धि की अनिश्चितता होगी और बढ़ते तापमान से वैश्विक फसलों की पैदावार कम होगी, जबकि महासागरों की वार्मिंग और अम्लीकरण समुद्री वन्य जीवन और मत्स्य पालन को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति जनता और सरकारों का उदासीन रवैया किस हद तक खतरनाक हो सकता है, इसके प्रति अभी तक न ही तो जनता जाग रही है और न ही सरकारें। मानव सभ्यता के विकास के लिए ढाई सौ साल पहले शुरू हुई औद्योगिक क्रांति के कारण जलवायु का संतुलन बिगड़ना शुरू हुआ जो एक गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है। पिछले कुछ समय में अति वर्षा, लगातार पिघलते ग्लेशियरों के कारण बनती नई झीलों, बाढ़, अधिक गर्मी और समुद्र का स्तर बढ़ने से चक्रवाती गतिविधियों जैसे दर्शनीय तथ्यों ने न सिर्फ सरकारों, बल्कि आम जनता का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट करना शुरू किया है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के इन प्रत्यक्ष परिणामों के बाद भी अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण में आ रहे बदलावों को न ही समझते हैं और न ही इसे समझाने के लिए अभी तक व्यापक स्तर पर कोई जन-जागरण अभियान चलाया गया है।

बढ़ता तापमान समुद्री लहरों की प्रमुख व्यवस्था अटलांटिक मेरिडौनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन को पिघलती ध्रुवीय बर्फ के ताजा पानी से जोड़कर कमजोर कर रहा है. इससे समुद्र का पानी पतला हो जाता है और गर्म पानी का उत्तर की ओर प्रवाह कम हो जाता है. इस फेरबदल से भारी वर्षा वाले इलाके बदल सकते हैं और भारतीय मॉनसून को कमजोर कर सकते हैं. इससे पूरे उपमहाद्वीप में लू और सूखे में तेजी आ सकती है. हालांकि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में मौसम की चरम स्थितियों की वजह है, लेकिन हर देश की विकास गतिविधियां स्थानीय वजह बनती हैं. शहरीकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और पहाड़ी ढलानों पर बस्तियां तथा कंक्रीट निर्माण बढ़ते भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आपदा को और बढ़ा देते हैं. इसके नजारे आज भारत में खुलकर दिखाई देते हैं. हिमाचल और उत्तराखंड में राजमार्गों, सुरंगों और बांधों के कारण नाजुक ढलानें और भी कमजोर हो गई हैं, जो अत्यधिक वर्षा के कारण ढह रही हैं, पूरे के पूरे गांवों को दफना रही हैं इस साल अगस्त में उत्तराखंड के धराली में एक बरसाती धारा प्रचंड बाढ़ में बदल गई, जो नदी के किनारे बनी दुकानों और घरों को बहा ले गई. पर्यावरण एक्टिविस्ट, शोधकर्ता तथा हिमाचल स्थित हिमधारा कलेक्टिव की सह-संस्थापक मानषी आशेर कहती हैं, ''नदी के पेटे में मकान वगैरह बनाए गए तो नदी ने अपनी जगह वापस ले ली.'' राजस्थान, पंजाब और हरियाणा एक महीने प्रचंड लू तो दूसरे में बाढ़ से पस्त हैं. मुर्तुगुड्डो कहते हैं, ''जलवायु परिवर्तन मौसम की चरम घटनाओं की अवधि, बारंबारता, पैमाने और तीव्रता को बढ़ाकर मामला संगीन बना रहा है.''

बार और तीव्र वर्षा हो रही है. इसीलिए राजस्थान में अगस्त २०२५ में अचानक बाढ़ आती देखी गई, जबकि पूर्वोत्तर के हरे-भरे इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं. उधर, देश की ११,०९८ किमी लंबी तटरेखा पर तूफान और चक्रवात तेज से तेजतर हो रहे हैं और ऊपर उठता समुद्र तल मुंबई, चेन्नै और कोलकाता सरीखे शहरों के लिए खतरा पैदा कर रहा है.

दुनिया में भी हालात खतरे के निशान से ऊपर हैं. विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने २०२४ को पहला ऐसा साल घोषित किया जब औसत वैश्विक तापमान औद्योगिक युग से पहले के स्तर से १.५ डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया, जो पेरिस जलवायु समझौते में तय सीमा है. रिकॉर्ड रखे जाने के १७५ साल में यह सबसे गर्म साल भी था. पिछले १० साल में हरेक साल सबसे गर्म साल दर्ज हुआ है. भारत में पिछले १२० साल के १० सबसे गर्म साल सभी पिछले १५ साल दर्ज हुए हैं. धरती तेज रफ्तार से गर्म हो रही है और भारत उसका दंश झेल रहे देशों में है. मोहंती आगाह करते हैं, ''हमारे लिए २ डिग्री सेल्सियस के नतीजों पर विचार करना जरूरी हो गया है क्योंकि मौजूदा रफ्तार से देश पर्याप्त तेजी से अपने को उसके अनुरूप नहीं ढाल पाएगा.''

क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (सीआरओपीसी) के अध्यक्ष प्रो. संजय श्रीवास्तव बताते हैं कि पंजाब को अप्रैल में ही बाढ़ के खतरे के बारे में चेतावनी दी गई थी, फिर भी उसके पास कोई कार्ययोजना नहीं थी. वे कहते हैं, ''यह मानसिकता ही देश की सबसे बड़ी सामाजिक-व्यावहारिक समस्या है कि कुछ नहीं होगा. स्थानीय निकायों और लोगों के बीच सुरक्षा की संस्कृति युद्धस्तर पर विकसित की जानी चाहिए. पूर्व चेतावनियों के बावजूद समस्या स्थानीय अधिकारियों के क्रियान्वयन और लोगों के जरिए अमल करने में आती है.'' आपदाओं के नुक्सान को कम करने को ध्यान में रखकर शहरी योजनाओं में निर्माण, भवन, जल निकासी और बिजली आपूर्ति के नियमों को डिजाइन किया जाना चाहिए. लेकिन यह बड़ी चुनौती बनी हुई है. स्थानीय निकायों को अमूमन नो-बिल्ड जोन और संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी होती है, फिर भी असुरक्षित निर्माण को मंजूरी मिल जाती है या संबंधित लोगों के साथ मिलीभगत से सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन पर आंखें मूंद ली जाती हैं.

श्रीवास्तव बताते हैं, ''सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्थानीय निकाय पर्यावरण नियमों के कार्यान्वयन पर जोर नहीं देते और आम लोग अमल नहीं करते. यह स्थानीय निकायों, ठेकेदारों और नेताओं की मिलीभगत के कारण संभव हो रहा है. इसे रोकना होगा.'' शहरों को भी नया रूप देना होगा. विशेषज्ञ 'शहरी स्पंज' की बात करते हैं, जिसमें पार्क, फुटपाथ, वर्षा उद्यान और जल निकासी प्रणालियां हों, जो बारिश के पानी को सोख लें. मुर्तुगुड्डे कहते हैं, ''इसका उद्देश्य यह तय करना है कि गिरता पानी बहता रहे और बहता पानी ठहरे.''

उतना ही महत्वपूर्ण राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों (एसडीआरएफ) को मजबूत करना भी है. उनकी प्राथमिक भूमिका आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य करना है, लेकिन आपदा के अलावा उनके कार्यों में लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करना और निकासी रणनीतियों, वैकल्पिक आश्रयों और बचाव मार्ग तैयार करना शामिल है. हालांकि, सभी मौसम की भारी मार वाली घटनाओं के लिए लोगों को वहां से निकालने की रणनीतियां होनी चाहिए. 'ऐसी रणनीति फिलहाल भारत में सिर्फ चक्रवात के दौरान समुद्री तटों के लिए है. बाढ़ के मामले में ऐसी कोई रणनीति नहीं है.■

- मीना. सिंह, एम.नटराजन